पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सनी देवी

बनाम

राम बाबू कुमार

2019 की विविध अपील संख्या 287

15 सितंबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी.भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या पक्षकारों के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(घ)के तहत इस आधार पर रद्द किया जा सकता था कि विवाह के समय पत्नी पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी, और क्या विवाह के चार महीने के भीतर पैदा हुए बच्चे को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 के अनुसार वैध माना जा सकता है?

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 12(1)(घ) - विवाह के समय धोखाधड़ी या छिपाव – पितृत्व विवाद - जहाँ विवाह के समय पत्नी गर्भवती थी और बच्चा चार महीने के भीतर पैदा हुआ था, धोखाधड़ी/अवैधता का आरोप लगाने वाले पति को ठोस सबूतों से यह स्थापित करना होगा कि गर्भाधान विवाह से पहले हुआ था और उसकी कोई पहुँच नहीं थी।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 112 - वैधता का निर्णायक प्रमाण - वैध विवाह के जारी रहने के दौरान पैदा हुए बच्चे को निर्णायक रूप से वैध माना जाता है, जब तक कि पक्षों के बीच पहुँच न होने का प्रमाण न मिल जाए। केवल संदेह या शंका वैधानिक अनुमान को विस्थापित नहीं कर सकती।

चिकित्सा साक्ष्य बनाम धारा 112 के तहत अनुमान - हालाँकि चिकित्सा साक्ष्य पूर्ण-कालिक प्रसव का संकेत देते हैं, विवाह से पहले पहुँच न होने के स्पष्ट प्रमाण या किसी विश्वसनीय खंडन के अभाव में, धारा 112 के तहत वैधता का अनुमान प्रबल होता है।

साक्ष्य का भार - धारा 12 एचएमए के तहत विवाह-विच्छेद की मांग करने वाले पति पर धोखाधड़ी, मिथ्याबयान या छिपाव को साबित करने का भारी भार होता है। विश्वसनीय मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने पर दावा टिक नहीं पाता।

पारिवारिक न्यायालय का निष्कर्ष - पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी को धोखाधड़ी का दोषी ठहराते हुए विवाह को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने, पुनर्मूल्यांकन पर, यह माना कि निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित था, कानूनी साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं था, और धारा 112 की धारणा के विपरीत था।

बच्चे की वैधता - स्थिति का संरक्षण - कानून बच्चों की वैधता की रक्षा के पक्ष में है; साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत वैधता की धारणा को मान्यताओं या संभावनाओं से हल्के में नहीं लिया जा सकता।

अपील - विवाह-विच्छेद के आदेश में हस्तक्षेप - धोखाधड़ी के सबूत के अभाव में, उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद के आदेश को रद्द कर दिया; पक्षों के बीच विवाह को वैध माना गया।

न्याय दृष्टान्त

एआईआर 1965 एससी 364; 1981, मध्य प्रदेश श्रृंखला **585; (1987) 1 एससीसी 624; (1993) 3 एससीसी 418; (2001) 12 एससीसी 311 ; (2009) 12 एससीसी 454; 2010 (2) एमडब्ल्यूएन (दीवानी) 337 ; 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 161; 2013 एससीसी ऑनलाइन केआर 24493**

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम; 1955; भारतीय साक्ष्य अधिनियम; 1872; पारिवारिक न्यायालय अधिनियम; 1984

मुख्य शब्दों की सूची

धता का निर्णायक प्रमाण; पितृत्व विवाद, बच्चे की वैधता; गैर-पहुंच, सबूत का भार; वैधता की धारणा; चिकित्सा साक्ष्य बनाम वैधानिक अनुमान; पारिवारिक न्यायालय के आदेश का निरस्तीकरण; उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप; विवाह की वैधता; बच्चे की स्थिति का संरक्षण; संदेह बनाम प्रमाण।

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 250/2012 में पारिवारिक न्यायालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.04.2019 को पारित निर्णय

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री शिव शंकर शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं की ओर से: श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: रवि राज, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की विविध अपील संख्या. 287

==========

सन्नी देवी, पति - राम बाबू कुमार, पिता - सुदिश प्रसाद, गाँव - मल्लाही बाजार, डाकघर और थाना -मलाही, जिला - पूर्वी चंपारण ।

अपीलार्थी/ओं

बनाम

राम बाबू कुमार, पिता - महंथ प्रसाद, गाँव- सुनारपुर, थाना -ब्रंजारिया, जिला - पूर्वी चंपारण,गाँव - सिंघिया हिवन ब्रंजारिया जिला - पूर्वी चंपारण।

.

उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री शिवशंकर शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सी.ए.वी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

दिनांक :15-09-2023

वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत, जोकि दिनांक 18.04.2019 को प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ने 2012 के वैवाहिक (तलाक) मामले संख्या.250 को आक्षेपित करते हुए दायर

की गई है , जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 (डी) के तहत याचिकाकर्ता-उत्तरदाता द्वारा दायर याचिका में पक्षकारों के बीच विवाह को रद्द करने के लिए रद्द करने की डिक्री के लिए अनुरोध किया गया है, अनुमति दी गई है।

2. याचिकाकर्ता-उत्तरदाता का मामला, के अनुसार पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि पूर्वी चंपारण जिले में स्थित गाँव मलाही बाज़ार में हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच 19.04.2012 को शादी का आयोजन किया गया था। दोनों पक्ष अंतिम बार परिवार न्यायालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में स्थित सुनारपुर में एक साथ रहे थे। यह भी माना जाता है कि वर्तमान याचिका से पहले याचिकाकर्ता-उत्तरदाता द्वारा कोई याचिका दायर नहीं की गई है और वैवाहिक याचिका प्रस्तुत करने के लिए पक्षों के बीच कोई मिलीभगत नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के बाद, प्रतिवादी-अपीलार्थी अपने वैवाहिक घर में शामिल हो गया। यह आगे बताया गया है कि जल्द ही प्रतिवादी-अपीलार्थी ने याचिकाकर्ता-उत्तरदाता के साथ दुर्व्यवहार करना और उसके साथ को नापसंद करना शुरू कर दिया और उसके साथ रहने से भी इनकार कर दिया। यह आगे बताया गया है कि 30.04.2012 को , याचिकाकर्ता-उत्तरदाता ने प्रतिवादी-अपीलार्थी के गर्भवती होने के विभिन्न लक्षण देखे थे। प्रतिवादी-अपीलार्थी ने गर्भावस्था के संकेत को दबाने के इरादे से अकेले रहने की कोशिश की। यह आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ता-उत्तरदाता ने प्रतिवादी-अपीलार्थी के शरीर और व्यवहार की असामान्यता को देखकर, प्रतिवादी-अपीलार्थी का गर्भावस्था परीक्षण कराया, जो सकारात्मक पाया गया। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी-अपीलार्थी ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार किया और शादी से पहले दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध स्वीकार किए। यह आगे बताया गया है कि 07.06.2012 को शिकायत पर, प्रतिवादी-अपीलार्थी के पिता

और भाई सिंघिया हिवन आए और याचिकाकर्ता-उत्तरदाता से कहा कि उसका संदेह गलत है और उन्होंने उसे प्रतिवादी-अपीलार्थी का अल्ट्रासाउंड परीक्षण कराने की सलाह दी। सलाह के अनुसार, प्रतिवादी-अपीलार्थी का अल्ट्रासाउंड परीक्षण एच. आई. टेक स्कैन सेंटर जनपुल चौक, मोतिहारी में 08.06.2012 को किया गया था और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चला कि भ्रूण की आयु आठ सप्ताह है, जिसका अर्थ है कि बच्चे की कल्पना शादी की तारीख से पहले की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता शादी से पहले प्रतिवादी से कभी नहीं मिला था। यह आगे बताया गया है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद, प्रतिवादी-अपीलार्थी के भाई और पिता उसे अपने साथ अपने घर ले गए और इस बार, प्रतिवादी-अपीलार्थी उसके सभी गहने और अन्य सामान अपने साथ ले गया। इसलिए, वह दावा करता है कि विवाह अमान्य है और याचिकाकर्ता-उत्तरदाता-पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह से पहले से गर्भावस्था के आधार पर रद्द किया जा सकता है। इसलिए,याचिकाकर्ता-उत्तरदाता ने पक्षों के बीच विवाह को रद्द करने के लिए निरर्थकता के आदेश के लिए प्रार्थना की।

3. नोटिस पर, प्रतिवादी-अपीलार्थी परिवार न्यायालय के समक्ष पेश हुई और अपना लिखित बयान दायर किया जिसमें उसने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और उसने दावा किया है कि शादी के अगले ही दिन पक्षों के बीच शारीरिक संबंध थे, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसने आगे कहा है कि शादी 19.04.2012 पर की गई थी और एक लड़की का जन्म 22.01.2013 पर हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी-अपीलार्थी के खिलाफ आरोप गलत है। उसने आगे बयान दिया कि बच्चे का जन्म रेफरल अस्पताल, अरेराज में हुआ था। उसने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता-उत्तरदाता द्वारा बेदखल किए जाने के बाद, वह अपने मायाके में रह रही थी। उसने आगे दावा किया है कि उसके भाई सुग्रीम प्रसाद की पत्नी सुनीत देवी के

साथ उसके अवैध संबंधों के कारण उसके खिलाफ यह निराधार आरोप लगाया गया है। उसने यह भी दावा किया है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद, याचिकाकर्ता-उत्तरदाता को पता चला कि बच्चा स्त्रीलिंग है, उसने उस पर गर्भपात के लिए दबाव डाला, लेकिन वह गर्भपात के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए, उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि दहेज की अवैध मांग की गई थी और उसे पूरा न करने के कारण, उसे 12.09.2012 पर वैवाहिक घर से निकाल दिया गया था और इसलिए, 20.12.2012 पर शिकायत दर्ज की गई थी। उसने आगे दावा किया है कि उसने याचिकाकर्ता-उत्तरदाता के साथ शादी से पहले किसी के साथ कभी यौन संबंध नहीं बनाए थे और उसने प्रार्थना की है कि याचिका को जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

4. पक्षों की दलीलों के आधार पर, विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे :

(i) क्या याचिका, जैसा कि तैयार किया गया है, बनाए रखने योग्य है।

(ii) क्या प्रतिवादी विवाह से पहले किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी और यह उत्तरदाता की जानकारी में नहीं था।

(iii) क्या उत्तरदाता ने अपनी गर्भावस्था के बारे में जानने के बाद प्रतिवादी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।

(iv) क्या उत्तरदाता किसी राहत का हकदार है।

5. मुकदमे के दौरान, वादी-उत्तरदाता ने खुद को एकमात्र गवाह के रूप में परीक्षित किया, जबकि प्रतिवादी-अपीलार्थी ने भी अपने मामले के बचाव में खुद को एकमात्र गवाह के रूप में परीक्षित किया था।

6. एकमात्र उत्तरदाता गवाह राम बाबू कुमार, जो स्वयं

उत्तरदाता हैं, अ. सा.-1 के रूप में पूछताछ की गई है। मुख्य जांच में , उन्होंने अपनी याचिका में दिए गए अपने बयान को दोहराया है। जिरह में, उसने बयान दिया है कि प्रतिवादी-अपीलार्थी अपने घर पर नहीं है और न ही वह उसे अपने घर पर रखेगा। प्रतिवादी-अपीलार्थी की एक बेटी है, जिसका जन्म शादी के बाद हुआ था। उसने इस आरोप से इनकार किया था कि उसने अपनी पत्नी को पीटा और उसका सामान छीन लिया। वह स्वीकार करता है कि प्रतिवादी-अपीलार्थी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालाँकि, उसका दावा है कि उसने उससे पहले अपना मामला दर्ज कराया है। उसने यह भी बयान दिया है कि वह बच्चे के डी.एन.ए परीक्षण के लिए तैयार है। उन्होंने इस आरोप से इनकार किया कि उनके भाभी के साथ अवैध संबंध हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसकी पत्नी के किसके साथ अवैध संबंध हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध को अपनी आंखों से नहीं देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह उन लोगों के नाम नहीं बता सकते जिन्होंने उन्हें उनकी पत्नी के बुरे चरित्र के बारे में बताया है। उसने आगे कहा कि वह एक सरकारी शिक्षक है और उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही है। उसने यह भी बयान दिया है कि उसके ससुर नहीं रहे और प्रतिवादी-अपीलार्थी-पत्नी अपनी माँ के साथ रह रही है। उसने यह भी अपदस्थ कर दिया है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में सक्षम है, हालाँकि, उसकी पत्नी मायाके में एक दयनीय जीवन जी रही है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें 19,000/- प्रति माह का वेतन मिलता है। उसने आगे कहा है कि उसे पता नहीं है कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी की है या नहीं। वह उससे छुटकारा पाना चाहता है ताकि वह फिर से शादी कर सके। उन्होंने इस आरोप से भी इनकार किया कि उन्होंने यह याचिका पुनर्विवाह के उद्देश्य से दायर की है।

7. प्रतिवादी सन्नी देवी ने अपने मामले का समर्थन

करने के लिए खुद को एकमात्र प्रतिवादी गवाह के रूप में पेश किया है। उनके मुख्य परीक्षण को हलफनामे के माध्यम से दाखिल किया गया है। उक्त हलफनामे में, उन्होंने अपने लिखित बयान में दिए गए अपने बयान को दोहराया है। उसने यह भी बयान दिया है कि उसकी बेटी वर्तमान में पाँच साल की है। उसने यह भी बयान दिया है कि उसने 2014 की सं. 312 वाले रखरखाव के मामले के साथ-साथ 2017 का सं. 14 वाले उत्पीड़न के मामले भी दायर किए हैं। जो वर्तमान में माननीय विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक समाहर्ता, मोतिहारी की न्यायालय में लंबित है। उसने यह भी बयान दिया है कि उसे अपने और अपने बेटी लिए प्रति माह 5,000/- के रखरखाव के भुगतान के लिए न्यायालय का आदेश मिला है,जोकि उसके पति द्वारा भुगतान किया जा रहा है। उसने आगे कहा कि उसके और उसकी बेटी की देखभाल करने के लिए उसके पति के अलावा कोई नहीं है क्योंकि उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।

7(i) अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने बयान दिया है कि वह पिछले पांच वर्षों से अपने पति से अलग है और उसने उत्पीड़न के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया है और उसके पति इस संबंध में जेल भी जा चुका है । उसने यह भी बयान दिया है कि उसके ससुर की हत्या कर दी गई है और उसने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। उसने आगे कहा कि उसे नियमित रूप से रखरखाव का भुगतान नहीं मिलता है। कभी-कभी उसे भुगतान मिलता है, लेकिन कभी-कभी नहीं।

8. अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता की याचिका को यह पाते हुए पक्षकारों के बीच विवाह को अमान्य घोषित करने की अनुमति दी गई है कि पक्षकारों के बीच विवाह को 19.04.2012 संपन्न किया गया था और विवाह के बाद अपीलार्थी-पत्नी प्रतिवादी-पति के वैवाहिक घर में शामिल हो गई और प्रतिवादी-पति द्वारा

व्यक्त किए गए संदेह पर, अपीलार्थी-पत्नी पर उसकी गर्भावस्था का परीक्षण करने के लिए को 08.06.2012 अल्ट्रासाउंड किया गया था और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार, वह आठ सप्ताह की गर्भवती पाई गई थी। यह आगे पाया गया है कि अल्ट्रासाउंड के बाद,अपीलार्थी-पत्नी को उसके भाई और पिता अपने घर ले गए थे। यह आगे विद्वान् न्यायधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा पाया गया है और उन्होंने कहा कि 08.06.2012 को , वैवाहिक गृह में अपीलार्थी-पत्नी का दो महीने का समय पूरा नहीं हुआ था और इसलिए अपीलार्थी-पत्नी का दो महीने की गर्भवती होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह विवाह से पहले से गर्भवती थी। उत्तरदाता-पति को शादी के समय इस गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था। यह भी पाया गया है कि शादी से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई सहवास नहीं था। इसलिए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर, माननीय विद्वान् न्यायधीश पारिवारिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वह उत्तरदाता-पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह से पहले से ही गर्भवती थी। इसलिए, विवाह को अमान्य घोषित किया गया था।

9. अपीलार्थी के लिए विद्वान् अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि माननीय विद्वान् न्यायधीश पारिवारिक न्यायालय तथ्यों और कानून को ठीक से समझने में विफल रहे है और इसलिए न्यायालय त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि हालांकि इस मामले में बच्चे की वैधता स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, लेकिन इसमें शामिल मुद्दे पर न्यायालय के निष्कर्ष का पत्नी के साथ-साथ बच्चे के लिए भी गंभीर परिणाम होना तय है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि माननीय विद्वान् न्यायधीश परिवार न्यायालय यह समझने में विफल रहे है कि अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भावस्था परीक्षण बच्चे के गर्भधारण की सटीक तारीख का सटीक पता नहीं लगा सकता है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि बच्चे का जन्म अपीलार्थी-पत्नी के विवाह के बाद वैवाहिक घर में प्रतिवादी-पति में

शामिल होने के 278 दिनों के भीतर होता है, यानी 20.04.2012 को और तब से 12.09.2012 तक उनके बीच सहवास था, जब उसे उसके द्वारा बेदखल कर दिया गया था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि पक्षकारों के बीच पहले सहवास के 278 दिनों के भीतर महिला बच्चे का जन्म हुआ था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार, इस बात का निर्णायक प्रमाण है कि बच्चे का जन्म पक्षकारों से हुआ है। इस निर्णायक प्रमाण का उत्तरदाता-पति द्वारा अपीलार्थी-पत्नी तक पहुँच न होने को साबित करके खंडन नहीं किया गया है। केवल पति का यह कथन कि उसने कभी भी अपीलार्थी-पत्नी के साथ सहवास नहीं किया है, गैर-संपर्क साबित करने के लिए दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

10. हालाँकि, उत्तरदाता-पति के विद्वान् अधिवक्ता , माननीय विद्वान् न्यायधीश द्वारा पारित निर्णय का बचाव करते हैं। पारिवारिक न्यायालय ने कहा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखते हुए, शादी के दौरान बच्चे की कल्पना नहीं की गई थी और अपीलार्थी-पत्नी शादी से पहले से ही गर्भवती थी और इसलिए माननीय विद्वान् न्यायधीश ,पारिवारिक न्यायालय द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है उत्तरदाता-पति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए और विवाह को अमान्य घोषित करने के दौरान।

11. पक्षकारों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैंः

(i) क्या अपीलार्थी-पत्नी विवाह के समय उत्तरदाता-पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी।

(ii) क्या उत्तरदाता-पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) (डी) के तहत निरर्थकता की डिक्री द्वारा अपीलार्थी के साथ अपने विवाह को अमान्य घोषित करने का हकदार है।

12. इससे पहले कि हम निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ें, वैवाहिक मामलों में

सबूत साबित करने की जिम्मेदारी और सबूत के मानक के संबंध में मामले के कानूनों या आधिकारिक न्यायिक घोषणाओं को देखना अनिवार्य है।

13. **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने विस्तार से कहा है कि वैवाहिक मामलों में **डॉ. नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने, जैसा कि 1975 में रिपोर्ट किया गया था (2) एस. सी. सी. 326 सबूत को साबित करने की जिम्मेदारी** की प्रकृति पर चर्चा की गई और निर्धारित कानून यहाँ अभी भी कायम रहा है। मामले के कंडिका 23 में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा है कि, निस्संदेह, अपने मामले को स्थापित करने का भार याचिकाकर्ता पर होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर, भार उस पक्ष पर होता है जो किसी तथ्य की पुष्टि करता है, न कि उस पक्ष पर जो इसे नकारता है। यह सिद्धांत सामान्य ज्ञान के अनुरूप है क्योंकि नकारात्मक की तुलना में सकारात्मक साबित करना बहुत आसान है। इसलिए याचिकाकर्ता को यह साबित करना चाहिए कि प्रतिवादी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है।

14. **प्रमाण के मानक** पर आते हुए, हम पाते हैं कि "वैवाहिक अपराध" शब्द के उपयोग के कारण कुछ गलत धारणा उत्पन्न हुई थी , हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रतिवादियों के दुर्व्यवहार का वर्णन करने के लिए उपयोगी है । यही कारण है कि आधिकारिक निर्णय से पहले माननीय **उच्चतम न्यायालय के माननीय पूर्ण पीठ** ने **डॉ. नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने मामले में,** जैसा कि **1975 (2) एस. सी. सी. 326 में** रिपोर्ट किया गया था, उसमे परस्पर विरोधी विचार थे। एक दृष्टिकोण के अनुसार, वैवाहिक मामले दीवानी प्रकृति के होते हैं और इसलिए ऐसे मामलों में प्रमाण का मानक संभावनाओं की अधिकता होगी, जबकि दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम में "वैवाहिक अपराध" शब्द के उपयोग को देखते हुए वैवाहिक मामलों में उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक होना चाहिए। तथापि, **डॉ. नारायण**

गणेश दास्ताने मामले (ऊपर) में, **उच्चतम न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ** ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि वैवाहिक मामले दीवानी प्रकृति के होते हैं और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैवाहिक मामलों के मुकदमे में संभावनाओं की अधिकता सबूत का मानक होगी, न कि उचित संदेह से परे सबूत जो आपराधिक मुकदमों में लागू होता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय,** के कंडिका 24 में **डॉ. नारायण गणेश दास्ताने मामले (ऊपर)** में कहा गया है कि दीवानी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला सामान्य नियम यह है कि एक तथ्य को स्थापित कहा जा सकता है यदि इसे संभावनाओं की अधिकता से साबित किया जाए। यही कारण है कि साक्ष्य अधिनियम, धारा 3 के तहत, तथ्य को तब साबित कहा जाता है जब न्यायालय या तो इसे अस्तित्व में मानती है या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानती है कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद है। इस प्रकार किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में विश्वास संभावनाओं के संतुलन पर आधारित हो सकता है। तथ्य-स्थिति के संबंध में परस्पर विरोधी संभावनाओं का सामना करने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति इस धारणा पर कार्य करेगा कि तथ्य मौजूद है, यदि विभिन्न संभावनाओं को मापने पर वह पाता है कि प्रधानता विशेष तथ्य के अस्तित्व के पक्ष में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के तरह , ये न्यायालय इस परीक्षण को यह पता लगाने के लिए लागू करती है कि क्या मुद्दे में एक तथ्य को साबित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पहला कदम संभावनाओं को ठीक करना है, दूसरा उन्हें मापना है, हालांकि दोनों अक्सर आपस में मिल सकते हैं। असंभव को पहले चरण में और असंभावित को दूसरे चरण में समाप्त कर दिया जाता है। संभावनाओं की विस्तृत श्रृंखला के भीतर न्यायालय को अक्सर एक कठिन विकल्प चुनना पड़ता है, लेकिन यह वह विकल्प है जो अंततः निर्धारित करता है कि संभावनाओं की प्रधानता कहाँ है। लेकिन क्या मुद्दा क्रूरता का है या एक प्रतिज्ञा पत्र पर ऋण का परीक्षण लागू करने के लिए यह है कि क्या संभावनाओं की अधिकता पर प्रासंगिक

तथ्य साबित होता है। दीवानी मामलों में यह, आम तौर पर, यह पता लगाने के लिए आवेदन करने के लिए सबूत का मानक है कि क्या सबूत का बोझ हटा दिया गया है।

15. वैवाहिक मामलों में "उचित संदेह से परे सबूत" के आवेदन को खारिज करते हुए, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय, डॉ. नारायण गणेश दास्ताने मामले के कंडिका 25 में (उपरोक्त)** ने पाया है कि उचित संदेह से परे प्रमाण एक उच्च मानक द्वारा प्रमाण है जो आम तौर पर अर्ध-आपराधिक प्रकृति के मुद्दों की जांच से जुड़े आपराधिक मुद्दे को नियंत्रित करता है। आपराधिक मुकदमे में विषय की स्वतंत्रता शामिल होती है जिसे केवल संभावनाओं की अधिकता पर नहीं हटाया जा सकता है। यदि संभावनाएं इतनी अच्छी तरह से संतुलित होती हैं कि एक विवेकपूर्ण, न कि एक अस्थिर, मन यह नहीं पा सकता है कि प्रमुखता कहाँ है, तो साबित किए जाने वाले तथ्य के अस्तित्व के बारे में संदेह उत्पन्न होता है और इस तरह के उचित संदेह का लाभ अभियुक्त को जाता है। विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति के परीक्षणों में इस तरह के विचारों को आयात करना गलत है। डॉ. नारायण गणेश दास्ताने मामला (ऊपर), के कंडिका 26 में , **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता को उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करना चाहिए। धारा 23 न्यायालय को डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करती है यदि वह अपनी उप-धारा (1) खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित मामलों पर "संतुष्ट" है। यह देखते हुए कि अधिनियम के तहत कार्यवाही अनिवार्य रूप से एक दीवानी प्रकृति की है, "संतुष्ट" शब्द का अर्थ संभावनाओं की अधिकता की प्रमुखता पर संतुष्ट" और" एक उचित संदेह से परे संतुष्ट नहीं होना चाहिए ,धारा 23 दीवानी मामलों में सबूत के मानक को नहीं बदलती है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने डॉ. नारायण गणेश दास्ताने मामले (उपरोक्त) के कंडिका 27 में आगे कहा है कि वैवाहिक

मामलों में सबूत के मानक के बारे में गलत धारणा शायद ऐसे मामलों में प्रतिवादी के आचरण के एक ढीले विवरण से उत्पन्न होती है जो एक "वैवाहिक अपराध" का गठन करता है। पति या पत्नी के ऐसे कार्य जिनका वैवाहिक संघ की अखंडता को खराब करने के लिए गणना की जाती है, उनका सामाजिक महत्व है। शादी करना या न करना और यदि ऐसा है तो किससे करना एक निजी मामला हो सकता है, लेकिन वैवाहिक बंधन तोड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। विवाह की संस्था में समाज की हिस्सेदारी है और इसलिए गलती करने वाले पति या पत्नी को केवल चूककर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक अपराधी के रूप में माना जाता है। लेकिन यह सामाजिक दर्शन, हालांकि इसका विवाह के विघटन के आधार के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले किसी आरोप के स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता पर असर पड़ सकता है, लेकिन वैवाहिक मामलों में सबूत के मानक पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है।

17. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 121** में दी गई सूचना के अनुसार, **शोभा रानी बनाम मधुखर रेड्डी** के कंडिका **10** में यह भी देखा गया है कि यह देखते हुए कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही अनिवार्य रूप से एक दीवानी प्रकृति की है, शब्द 'संतुष्ट' का अर्थ 'संभावनाओं की प्रधानता पर संतुष्ट' होना चाहिए और 'उचित संदेह से परे संतुष्ट' नहीं होना चाहिए। अधिनियम की धारा 23 दीवानी मामलों में सबूत के मानक को नहीं बदलती है।

18. **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने **ए. जयचंद्र बनाम अनील कौर** के कंडिका 10 में, जैसा कि **2005(2) एस. सी. सी. 22** में रिपोर्ट किया गया था यह देखा गया है कि विवाह जैसे नाजुक मानवीय संबंधों में, मामले की संभावनाओं को देखना पड़ता है। अवधारणा, संदेह की छाया से परे सबूत, आपराधिक मुकदमों पर लागू किया जाना चाहिए न कि दीवानी मामलों पर और निश्चित रूप से पति और पत्नी जैसे नाजुक व्यक्तिगत संबंधों के मामलों पर तो नहीं। इसलिए, किसी को

यह देखना होगा कि किसी मामले में क्या संभावनाएं हैं और कानूनी क्रूरता का पता लगाना होगा, न केवल तथ्य के रूप में, बल्कि दूसरे के कार्यों या चूक के कारण शिकायतकर्ता पति या पत्नी के दिमाग पर प्रभाव के रूप में। क्रूरता भौतिक या शारीरिक या मानसिक हो सकती है। शारीरिक क्रूरता में, ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन मानसिक क्रूरता के मामले में एक ही समय में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, अदालतों को साक्ष्य में सामने लाई गई घटनाओं की मानसिक प्रक्रिया और मानसिक प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से वैवाहिक विवाद में साक्ष्य पर विचार करना होगा।

19. माननीय केरल उच्च न्यायालय ने **ए. जयचंद्र मामले (उपरोक्त)** को संदर्भित करने के बाद, **मोहनदास पणिकर बनाम दक्षिणानी** के कंडिका 19 में, जैसा कि **2013 में एस.सी.सी ऑनलाइन केर 24493** में बताया गया था कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत दोहराते हैं कि दीवानी मामलों में, संभावनाओं की अधिकता मामले को साबित करने के लिए अपनाया जाने वाला मानक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैवाहिक मामले दीवानी कार्यवाही हैं और न्यायालय संभावनाओं की प्रधानता पर कार्य कर सकता है, विशेष रूप से व्यभिचारिक मामलों में, क्योंकि प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है।

20. आइए अब उन बिंदुओं पर विचार करें जिन्हें निर्धारण के लिए तैयार किया गया है।

बिंदु सं.1

21. इससे पहले कि हम इस बिंदु पर विचार करें, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा।

22. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा **12:**

"12. रद्द किए जाने वाले विवाह।

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह

*अमान्य होगा और निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी अमान्यता की डिक्री द्वारा रद्द किया जा सकता है, नामतः — **माननीय सर्वोच्च न्यायालय***

(ए).....

(बी) ....

(सी).....

*(घ) **कि उत्तरदाता विवाह के समय याचिकाकर्ता अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी।***

(2) उप-अनुभाग में निहित कुछ भी होने के बावजूद। (1), विवाह रद्द करने के लिए कोई याचिका नहीं -

(ए).....

(ख) उप-धारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट आधार पर सुनवाई तब तक की जाएगी जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो -

(i) कि याचिकाकर्ता विवाह के समय कथित तथ्यों से अनजान था;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले संपन्न विवाह के मामले में ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर और विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे प्रारंभ के बाद संपन्न विवाह के मामले में कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आधार के अस्तित्व का पता चलने के बाद से याचिकाकर्ता की सहमति से वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। "

23. इस प्रकार, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) (डी) के तहत, विवाह को रद्द करने की डिक्री द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि प्रतिवादी विवाह के समय याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। हालांकि तीन शर्तों को पूरा किया जाना है जो उप-धारा के खंड (बी) के उप-खंड (i) से (iii) में उल्लिखित हैं। (2) हिंदू विवाह

अधिनियम की धारा 12 । वे शर्तें इस प्रकार हैंः(i) कि याचिकाकर्ता शादी के समय के लगाए गए आरोपों के तथ्यों से अनजान था। (ii) अधिनियम के प्रारंभ से पहले संपन्न विवाह के मामले में ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर और विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिनियम के प्रारंभ के बाद संपन्न विवाह के मामले में कार्यवाही शुरू की गई है। इस प्रकार, इस खंड के तहत आवेदन दायर करने के लिए एक सीमा की अवधि तय की गई है, (iii) कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आधार के अस्तित्व का पता चलने के बाद से याचिकाकर्ता की सहमति से वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है।

24. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन इस खंड के तहत विवाह को रद्द करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-पत्नी की कथित गर्भावस्था की अज्ञानता और इस याचिका को दायर करने की सीमा के बारे में कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार, हमें केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या उत्तरदाता-पति ने यह साबित किया है कि विवाह के समय अपीलार्थी-पत्नी गर्भवती थी और क्या कथित गर्भावस्था का पता चलने के बाद पति-याचिकाकर्ता, जो इसमें उत्तरदाता है, की सहमति से वैवाहिक संभोग हुआ था।

25. इससे पहले कि हम इस संबंध में अभिलेख के साक्ष्य पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा, जो के निष्कर्ष रूप में कार्य करता है जिससे बच्चे की वैधता के मुद्दे पर सीधा असर पड़ता है।

26. साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **112:-**

*"112, **विवाह के दौरान जन्म, निर्णायक वैधता प्रमाण।** यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अपनी माँ और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के जारी रहने के दौरान पैदा हुआ था, या इसके विघटन के दो सौ अस्सी दिनों के भीतर, माँ का अविवाहित रहना, इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि वह उस व्यक्ति का वैध पुत्र है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि विवाह के*

पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब तक कि वह पैदा हो सकता था। "

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया** के कंडिका 34 में, जैसा कि **2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 161** में बताया गया है, कहा है कि यह कानून धारा 112 के नियम का प्रतीक है कि वैध विवाह के दौरान या उसके विघटन के बाद 280 दिनों के भीतर (यानी गर्भावस्था की अवधि के भीतर) बच्चे का जन्म इस बात का "निर्णायक प्रमाण" होगा कि बच्चा वैध है, जब तक कि यह सबूत द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है कि पति और पत्नी की किसी भी समय एक-दूसरे तक कोई पहुंच नहीं थी या नहीं हो सकती थी जब तक कि बच्चे की कल्पना की जा सकती थी। इस प्रावधान का उद्देश्य वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को निर्विवाद वैधता प्रदान करना है। जब वैध विवाह के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है, तो इसका मतलब यह होगा कि माता-पिता की एक-दूसरे तक पहुंच थी। इसलिए, यह धारा वैध विवाह की अवधि के दौरान बच्चे के वैध जन्म के "निर्णायक प्रमाण" की बात करती है।

28. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया मामले (ऊपर) के कंडिका 35 में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि खंड का अंतिम भाग बच्चे के माता-पिता की एक-दूसरे तक पहुँच न होने के प्रमाण के संदर्भ में है। इस प्रकार, बच्चे के जन्म की वैधता की धारणा का इसके विपरीत मजबूत साक्ष्य के माध्यम से खंडन किया जा सकता है।

29. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया मामले (ऊपर) के कंडिका 36 में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि धारा 112 में अंतर्निहित सिद्धांत उस बच्चे के पितृत्व के बारे में अनुचित जांच को रोकना है जिसके माता-पिता की प्रासंगिक समय पर एक-दूसरे तक "पहुंच" थी। दूसरे शब्दों में, एक बार जब किसी विवाह को वैध माना जाता है, तो उस विवाह से पैदा हुए बच्चों के वैध होने के बारे में एक मजबूत धारणा है। इस धारणा का खंडन केवल इसके विपरीत मजबूत,

स्पष्ट और निर्णायक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक नीति की धारणा पर आधारित है।

30. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया मामले **(ऊपर)** के कंडिका **37** में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि "पहुँच "या" पहुँच से बाहर "का अर्थ वास्तविक सहवास नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है यौन संबंधों के अवसरों का" अस्तित्व "या" गैर-अस्तित्व "। धारा 112 जन्म के समय को महत्वपूर्ण पहलू के रूप में संदर्भित करती है न कि गर्भधारण के समय के रूप में। गर्भधारण का समय केवल यह देखने के लिए प्रासंगिक है कि पति की पत्नी तक पहुंच थी या नहीं। इस प्रकार, विवाह के जारी रहने के दौरान जन्म वैधता का "निर्णायक प्रमाण" है जब तक कि बच्चे के जन्म के समय बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाने वाले पक्ष की "गैर-पहुंच" उक्त पक्ष द्वारा साबित नहीं की जाती है।

31. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया मामले (ऊपर) के कंडिका 38 में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को धारा 4 के तहत "निर्णायक प्रमाण" की परिभाषा के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को वैध बच्चा माना जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यह दिखाया गया है कि विवाह के पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चा पैदा हो सकता था या विवाह के विघटन के 280 दिनों के भीतर और माँ अविवाहित रहती है, यह तथ्य है। निर्णायक प्रमाण है कि बच्चा उस व्यक्ति का वैध पुत्र है। संबंधित समय पर गैर-पहुंच साबित करके निर्णायक धारणा के संचालन से बचा जा सकता है।

32. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया मामले (ऊपर) के कंडिका 39 में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के बाद के भाग से संकेत मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति

यह स्थापित करने में सक्षम है कि विवाह के पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चा पैदा हो सकता था, तो ऐसे बच्चे की वैधता से इनकार किया जा सकता है। अर्थात्, यह मजबूत और ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि गंभीर बीमारी या नपुंसकता के कारण उनके बीच पहुंच असंभव थी या उस अवधि के दौरान पक्षों के बीच यौन संबंध की कोई संभावना नहीं थी जब बच्चा पैदा हुआ होगा। इस प्रकार, जब तक पहुंच की अनुपस्थिति स्थापित नहीं होती है, वैधता की धारणा को विस्थापित नहीं किया जा सकता है।

33. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया मामले के कंडिका 40 में(ऊपर), **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि इस प्रकार, जहां पति और पत्नी एक साथ रहे हैं, और कोई नपुंसकता साबित नहीं हुई है, उनके विवाह से पैदा हुए बच्चे को निर्णायक रूप से वैध माना जाता है, भले ही पत्नी को उसी समय बेवफाई का दोषी दिखाया गया हो,। यह तथ्य कि एक महिला व्यभिचार में रह रही है, अपने आप में एक बच्चे की वैधता के पक्ष में निर्णायक धारणा को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, इस साक्ष्य के टुकड़े के प्रभाव ये है कि पति ने गर्भधारण की अवधि में पत्नी के साथ संभोग नहीं किया था, केवल विवाह में पैदा हुए बच्चे की अवैधता की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन यह धारा 112 के तहत वैधता की धारणा को जड़ से समाप्त नहीं कर पायेगा।

34. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया मामले (ऊपर) के कंडिका 41 **में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि धारा 112 के तहत अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब बच्चा एक वैध विवाह के जारी रहने के दौरान पैदा हुआ हो और अन्यथा नहीं। “संपर्क "या" संपर्कहीनता "यौन संभोग के संदर्भ में होना चाहिए जो कि यौन अर्थ में है और इसलिए, उस संकीर्ण अर्थ में। उदाहरण के लिए, संपर्क न केवल तब असंभव हो सकती है जब पति उस अवधि के दौरान दूर हो जब बच्चा पैदा हो सकता था या विभिन्न कारणों से नपुंसकता या अक्षमता के कारण या पति की मृत्यु के बाद से समय बीतने के

कारण। इस प्रकार, भले ही पति सहवास कर रहा हो, लेकिन पति और पत्नी के बीच संपर्क नहीं हो सकता है। सह-निवास के बावजूद गैर-पहुंच के उदाहरणों में से एक पति की नपुंसकता है। यदि पति की पहुंच है, तो पत्नी की ओर से व्यभिचार अवैधता के निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराएँगा ।

35. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया मामले के कंडिका 43 में(**ऊपर**), **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि एक वास्तविक डी. एन. ए. परीक्षण का परिणाम भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान की निर्णायकता से बचा नहीं जा सकता है। यदि गर्भधारण के समय पति और पत्नी एक साथ रह रहे थे, लेकिन डी. एन. ए. परीक्षण से पता चलता है कि बच्चे का जन्म पति से नहीं हुआ था, तो निर्णायकता निर्विवाद बनी रहेगी। जो साबित होगा, वह पत्नी की ओर से व्यभिचार है, हालाँकि, बच्चे की वैधता अभी भी कानून में निर्णायक होगी। दूसरे शब्दों में, एक वैध विवाह के निर्वाह के दौरान पैदा हुए बच्चे के पितृत्व की निर्णायक धारणा यह है कि बच्चा पति का है और इसका खंडन केवल डीएनए परीक्षण रिपोर्ट से नहीं किया जा सकता है। खंडन करने के लिए जो आवश्यक है वह उस समय गैर-पहुंच का प्रमाण है जब बच्चे का जन्म हो सकता था, यानी उसकी गर्भधारण के समय।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **थच्चिनामूर्ति बनाम शिवगामी** के कंडिका 18 में, जैसा कि **2010 (2)**में रिपोर्ट किया गया था **एम. डब्ल्यू. एन. (सिविल) 337** में पाया है कि कानून संतान की वैधता के पक्ष में दृढ़ता से मानता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 कानून के एक नियम का प्रतीक है वैध विवाह का जारी रहना या 280 दिनों के दौरान (गर्भधारण की अवधि के भीतर), पैदा हुआ बच्चा था। यह निर्णायक प्रमाण होगा कि यह वैध है जब तक कि यह स्पष्ट और मजबूत साक्ष्य द्वारा साबित नहीं हो जाता है कि पति और पत्नी को किसी भी समय कोई पहुँच नहीं थी और न ही हो सकती थी जब बच्चे का जन्म हो सकता था।

37. शाम लाल उपनाम कुलदिप बनाम संजीव कुमार और अन्य के कंडिका 9 में जैसा कि **(2009) 12 एस. सी. सी. 454** में बताया गया है , **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने पाया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 अंग्रेजी कानून पर आधारित है। धारा 112 अंग्रेजी कानून के नियम को दोहराती है कि बच्चे के पितृत्व की जांच करना अवांछनीय है जब माँ एक विवाहित महिला है और पति को उससे संपर्क करने की अनुमति थी। यदि पति के पास पहुंच है तो उसकी ओर से व्यभिचार अवैधता के निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराएगा।

38. कामती देवी (श्रीमती) और अन्य बनाम पोशी राम जैसा कि **(2001) 12 एस. सी. सी. 311** के कंडिका 10 में बताया गया है **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने देखा है कि हमें याद होगा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को ऐसे समय में लागू किया गया था जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डी.एन.ए.) के साथ-साथ राइबोन्यूक्लिक एसिड (आर.एन.ए.) परीक्षणों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति विधायिका के विचार में भी नहीं थी। एक वास्तविक डी. एन. ए. परीक्षण का परिणाम वैज्ञानिक रूप से सटीक कहा जाता है। लेकिन यह भी अधिनियम की धारा 112 की निर्णायकता से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पति और पत्नी गर्भधारण के समय एक साथ रह रहे थे, लेकिन डी. एन. ए. परीक्षण से पता चला कि बच्चे का जन्म पति से नहीं हुआ था, तो कानून में निर्णायकता निर्विवाद बनी रहेगी। यह पति के दृष्टिकोण से कठिन लग सकता है जो एक ऐसे बच्चे का पितृत्व धारण करने के लिए मजबूर होगा जिसमें वह निर्दोष हो सकता है। लेकिन ऐसे मामले में भी कानून निर्दोष बच्चे के पक्ष में झुकता है जिसमे उसकी अवैध संतान बनने से बचाता है , अगर उसकी माँ और उसका जीवनसाथी गर्भधारण के समय एक साथ रह रहे थे। इसलिए निर्णायकता का खंडन करने के लिए गैर-संपर्क के प्रमाण की डिग्री के बारे में सवाल का जवाब इस बात के प्रकाश में दिया जाना चाहिए कि ऊपर वर्णित संपर्क या गैर-संपर्क का क्या अर्थ है।

39. गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के कंडिका 21 में जैसा कि **(1993) 3 एस. सी. सी. 418** में रिपोर्ट किया गया है **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने पाया है कि यह धारा इस प्रसिद्ध उक्ति पर आधारित है - (पिता ,वह है जिसे विवाह प्रदर्शित करती है)। वैधता की धारणा यह है कि एक विवाहित महिला से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है, यह उस व्यक्ति पर पड़ता है जो अवैधता साबित करने में रुचि रखता है उसका का पूरा बोझ उसी पे आता है । कानून दोनों को मानता है कि एक विवाह समारोह वैध है, और यह कि प्रत्येक व्यक्ति वैध है। विवाह या गोद लेना (माता-पिता) को माना जा सकता है, सामान्य रूप से यह कानून बुराई और अनैतिकता के खिलाफ है मानता है ।

40. गौतम कुंडू मामले (ऊपर) के कंडिका 22 में**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि यह कानून की एक खंडन योग्य धारणा है कि वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ बच्चा वैध है, और ये कि माता-पिता के बीच संपर्क हुआ है। इस धारणा को केवल सबूतों की प्रबलता से विस्थापित किया जा सकता है, न कि केवल संभावनाओं के संतुलन से।

41. श्रीमती दुख्तार जहां बनाम मोहम्मद फारूक के कंडिका 12 में जैसा कि **(1987) 1 एस. सी. सी. 624** में बताया गया है **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने पाया है कि फैसले में देखी गई एक और गंभीर कमजोरी यह है कि माननीय विद्वान न्यायाधीश ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। धारा 112 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी माँ और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के दौरान या उसके विघटन के दो सौ अस्सी दिनों के भीतर पैदा हुआ था और माँ अविवाहित रहती है, तो इसे निर्णायक प्रमाण के रूप में लिया जाएगा कि वह उस व्यक्ति का वैध पुत्र है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि विवाह के पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक कोई संपर्क नहीं था जब तक कि वह पैदा हो सकता था। न्याय के आदेशों पर आधारित कानून के इस नियम में

हमेशा अदालतों को एक बच्चे की वैधता को बनाए रखने की दिशा में झुका दिया है। जब तक कि तथ्य इतने बाध्यकारी और निर्णायक न हों कि यह निष्कर्ष आवश्यक रूप से गारंटी करता हो कि बच्चा पिता से पैदा नहीं हो सकता था और इस तरह बच्चे की वैधता के परिणामस्वरूप पिता के साथ अन्याय होगा। अदालतों ने हमेशा हल्के में या जल्दबाजी में फैसला देने से परहेज किया है और वह भी, मामूली तथ्यों के आधार पर, जिसका प्रभाव एक बच्चे को अवैध संतान और उसकी मां को अपवित्र महिला के रूप में प्रचारित करने पर पड़ेगा।

42. नंदकिशोर बनाम मुनिबाई में, जैसा कि **1981 में मध्य प्रदेश श्रृंखला 585** में बताया गया था, **माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय** ने देखा है कि एक महिला के प्रति अभद्रता बहुत गंभीर प्रकृति का आरोप है। यदि आरोप स्थापित हो जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। न केवल यह कि ऐसी महिला की समाज में निंदा की जाए और उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों की नजरों में उसे नीचा दिखाया जाए, बल्कि एक बच्चे को भी पीड़ित किया जा सकता है, यदि कोई हो, तो उसे अवैध संतान कहा जा सकता है। इसलिए, ऐसे मामलों में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य की तुलना में अधिक ठोस और विश्वसन्नी य साक्ष्य की तलाश करना उचित होगा।

43. महेंद्र मणिलाल नानावती बनाम सुशीला महेंद्र नानावती, जैसा कि **ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 364** में बताया गया है**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा है कि गर्भावस्था की अनुमानित अवधि की गणना गर्भधारण से पहले मासिक धर्म के पहले दिन से की जाती है और इसी कारण से गर्भधारण की वास्तविक तिथि से गर्भावस्था की अवधि में 14 दिन जोड़े जाते हैं। काल्पनिक गणना के आधार पर, पूरी तरह से परिपक्व बच्चे का जन्म 280 दिनों के बाद होता है। गर्भधारण की तारीख के आधार पर, बच्चे का जन्म 265 और 270 दिनों के बीच होता है। भ्रूण का विकास निस्संदेह उसकी उम्र पर निर्भर करता है जैसा कि गर्भधारण की तारीख से गिना जाता है और यही कारण है कि प्रसूति विज्ञान पर किताबें ज्यादातर गर्भधारण के

बाद के दिनों या हफ्तों के आधार पर भ्रूण के विकास से संबंधित हैं, लगभग दो महीने की अवधि के लिए और उसके बाद वे तीसरे और लगातार महीनों के अंत के संबंध में इसके विकास को नोट करने लगे। यह इस तथ्य के कारण होना चाहिए कि उस समय तक गर्भावस्था की अवधि में लगभग एक पखवाड़े का अंतर भ्रूण के विकास के विवरण में पर्याप्त अंतर नहीं लाता है। आखिरकार, गर्भावस्था की अवधि के संबंध में भ्रूण के विकास के संबंध में पूरा ज्ञान बड़ी संख्या में मामलों पर विचार करने और फिर, भ्रूण के विकास के कुछ सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जो कि गर्भधारण की तिथि से संबंधित है।

44. अब इस मामले पर आते हुए, हम पाते हैं कि पक्षों के बीच विवाह 19.04.2012 पर संपन्न किया गया था और पत्नी अगले दिन उत्तरदाता-पति के वैवाहिक घर में शामिल हो गई थी, यानी 20.04.2012 और महिला बच्चे का जन्म 22.01.2013 पर होता है। इस प्रकार, गणना के बाद हम पाते हैं कि पत्नी के पति के साथ उसके वैवाहिक घर में शामिल होने के 278 दिनों के भीतर बच्चे का जन्म हुआ था। यहाँ, यह उल्लेख करना उचित होगा कि एक बच्चे की सामान्य गर्भावस्था अवधि 280 दिन है। 280 दिनों की इस सामान्य गर्भधारण अवधि को साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में भी शामिल किया गया है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि यह 280 दिन गर्भावस्था अवधि की ऊपरी सीमा है न कि निचली सीमा। बच्चा 280 दिनों से कुछ दिन पहले पैदा हो सकता है। इस प्रकार, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 278 दिनों के भीतर पैदा हुए बच्चे की कल्पना उस दिन या उसके बाद की गई है जब अपीलार्थी-पत्नी विवाह के बाद उत्तरदाता-पति के वैवाहिक घर में शामिल हुई थी।

45. इसलिए, यह निर्णायक रूप से साबित होता है कि प्रतिवादी ने बच्चे को जन्म दिया है। अपीलार्थी शादी से पहले से गर्भवती नहीं थी।

46. उपरोक्त निर्णायक सबूत केवल पति द्वारा यह साबित करने

से खंडन किया जा सकता है कि उसकी अपीलार्थी पत्नी तक कोई पहुंच नहीं थी।

47. इस संदर्भ में, हम पाते हैं कि उत्तरदाता-पति के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी-पत्नी 19.04.2012 को शादी के बाद 20.04.2012 को उत्तरदाता-पति के साथ शामिल हुई और अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था परीक्षण के बाद उसे उसके पिता और भाई 08.06.2012 पर अपने घर ले गए। हालाँकि, अपीलार्थी-पत्नी के अनुसार 20.04.2012 पर अपने पति के वैवाहिक घर में शामिल होने के बाद वह 12.09.2012 तक अपने वैवाहिक घर में बनी रही जब तक कि उसे प्रतिवादी-पति द्वारा बेदखल नहीं कर दिया गया। यहाँ तक कि 20.04.2012 से 08.06.2012 तक की स्वीकृत अवधि को देखते हुए भी, जिसके दौरान अपीलार्थी-पत्नी उत्तरदाता-पति के साथ अपने वैवाहिक घर में रहती थी, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता-पति को अपनी अपीलार्थी-पत्नी तक पहुँच थी जब पैदा हुआ बच्चा, पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में, यह दिखाने की जिम्मेदारी पति पर होती है कि उसकी कोई पहुंच नहीं थी। हम पहले ही देख चुके हैं कि पहुँच का मतलब आवश्यक रूप से वास्तविक सहवास नहीं है। यह केवल सहवास के अवसर के बराबर है। इसलिए, उत्तरदाता-पति के इस कथन का कि अपीलार्थी-पत्नी के साथ उनका कोई सहवास नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई अर्थ नहीं है कि अपीलार्थी-पत्नी 20.04.2012 से 49 दिनों तक उनके साथ रही। जब उसकी अपनी पत्नी तक पहुँच थी। ऐसी स्थिति में, वह केवल नपुंसकता, गंभीर बीमारी या अपीलार्थी-पत्नी के साथ सहवास की असंभवता का अनुरोध करके ही गैर-पहुंच साबित कर सकता था। लेकिन पति की ओर से ऐसी कोई दलील या सबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी-पति को निर्णायक सबूत का खंडन करने की अनुमति नहीं है। बच्चे के पितृत्व पर विवाद करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक या अन्य प्रमाण स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अन्यथा भी, अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भावस्था परीक्षण पूरी तरह से सटीक नहीं है। इस तरह के परीक्षण के आधार पर कोई यह दावा नहीं कर सकता कि बच्चे की सटीक रूप से किस

तारीख को कल्पना की गई थी। हमेशा कुछ दिनों की त्रुटि की संभावना रहती है।

48. इस प्रकार हम पाते हैं कि अपीलार्थी-पत्नी शादी की तारीख को गर्भवती नहीं थी। उसने 20.04.2012 से 08.06.2012 के दौरान बच्चे की कल्पना की जब वह वैवाहिक घर में अपने पति के साथ रह रही थी और जब दोनों के पास एक-दूसरे तक पहुंच थी।

49. साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को लागू किए बिना भी, हम पाते हैं कि प्रतिवादी-पति के मामले में कोई दम नहीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भावस्था परीक्षण बच्चे की गर्भधारण की सटीक तारीख निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से सही तकनीक नहीं है। यही कारण है कि परीक्षण में निष्कर्ष सप्ताह की अवधि में दिए जाते हैं न कि दिनों में और यहां तक कि सप्ताह में, त्रुटि की गुंजाइश है। यदि हम 20.04.2012 से 08.06.2012 तक की अवधि की गणना करते हैं, जिसके दौरान दोनों पक्ष एक साथ रह रहे थे, तो यह 49 दिन यानी सात सप्ताह होगा, जो आठ सप्ताह से सिर्फ एक सप्ताह कम है। गर्भावस्था परीक्षण में हमेशा इस तरह की त्रुटि की गुंजाइश होती है।

50. इसके अलावा, बच्चे और प्रतिवादी-पिता की कोई डीएनए परीक्षण रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है। हालांकि साक्ष्य के दौरान, हम पाते हैं कि प्रतिवादी-पति डी. एन. ए. परीक्षण के लिए तैयार था, लेकिन उसने कभी विद्वान् न्यायधीश ,पारिवारिक न्यायलय इस तरह के परीक्षण के निर्देश के लिए को कभी आवेदन नहीं किया। जबकि यह साबित करने की जिम्मेदारी उस पर थी कि उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, हालांकि हमें डर है कि वह उस अवधि के दौरान अपनी पत्नी की गैर-पहुंच साबित किए बिना ऐसा निर्देश प्राप्त कर सकता था जब बच्चे की कल्पना की जा सकती थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को देखते हुए बच्चे के पितृत्व की जांच करना निषिद्ध है। हमारा कानूनी ढांचा एक बच्चे की वैधता के पक्ष में झुकता है और उसकी अवैध संतान होने पर नाराजगी जाहिर करता है। पति को दृढ़ता से

अपनी पत्नी से पैदा हुए बच्चे का पिता माना जाता है। इस धारणा का खंडन केवल तभी किया जा सकता है जब पति यह साबित करे कि उस अवधि के दौरान पति और पत्नी की एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चे की कल्पना की जा सकती थी।

51. इसलिए 112 साक्ष्य अधिनियम को लागू किये बिना भी , हम पाते हैं कि अपीलार्थी-पत्नी शादी की तारीख से पहले गर्भवती नहीं थी।

52. अब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (2) (बी) (iii) में प्रदान की गई शर्त के अनुपालन पर आते हुए, पति को यह भी साबित करना आवश्यक है कि विवाह की अकृतता के लिए दावा किए गए आधार की जानकारी के बाद, उसने अपीलार्थी-पत्नी के साथ कोई वैवाहिक संभोग नहीं किया था। याचिका को बनाये रखने के लिए ऐसी शर्त का पालन प्रतिवादी-पति द्वारा किया गया है, जो परिवार न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता थे, यह दलील और बयान देकर कि 08.06.2012 को अल्ट्रासाउंड परीक्षण के बाद, पत्नी को उसके पिता और भाई द्वारा वैवाहिक घर से अपने घर ले जाया गया था।

प्वाइंट नं. 2

53. बिन्दु संख्या.1 के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता-पति अपीलार्थी-पत्नी के साथ अपनी शादी को अमान्य घोषित करने का हकदार नहीं है।

54. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में स्थाई और मान्य नहीं है। आक्षेपित निर्णय जोकि दिनांक 18.04.2019, माननीय विद्वान् प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा पारित किया गया 2012 के वैवाहिक (तलाक) मामले संख्या 250 को रद्द कर दिया गया है। 2019 की विविध अपील संख्या 287,को स्वीकार किया गया है । हालांकि, दोनों पक्ष अपनी लागत खुद वहन करेंगे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

(जितेंद्र कुमार, न्यायामूर्ति)

(पी.बी.भजंत्री, न्यायामूर्ति)

अमरेंद्र/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।